# सांख्यिकी और रिज़र्व बैंक: कुछ विचार *

दीपक मोहन्ती

उपगवर्नर महोदय डॉ. सुबीर गोकर्ण तथा के.सी चक्रवर्ती, शिक्षा जगत के प्रख्यात सांख्यिकीशास्त्री तथा अर्थशास्त्री महोदयगण, चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक, चयनित विभागों के अध्यक्ष, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआइएम) के प्रभारी अधिकारी श्री ए.बी. चक्रवर्ती तथा मित्रो। सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआइएम) की वार्षिक कान्फ्रेन्स 2012 में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहली बार यह कान्फ्रेन्स भारतीय रिज़र्व बैंक के बाहर आयोजित की जा रही है जिससे कि आपस में घुलने-मिलने और मस्तिष्क मंथन का एक ऐसा अनौपचारिक वातावरण मिलेगा जो कि इस प्रकार की अनुसंधान कान्फ्रेन्स के लिए ज़रूरी होता है। यह सम्मेलन डीएसआइएम के अधिकारियों को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जिस पर वे विशेषज्ञों के समक्ष, अपने अनसंधान कार्य प्रस्तुत कर सकें और उनसे फीडबैक प्राप्त कर सकें ताकि नीति और रिसर्च के लिए, विश्लेषण को और अधिक सार्थक बनाया जा सके। मैं प्रख्यात प्रोफेसरगण का आभार मानता हूं कि उन्होंने डीएसआइएम में मेरे साथियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पर्चों पर चर्चा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की; प्रो. मनोज पाण्डा (सीईएसएस, हैदराबाद), प्रो. एन.आर. भानुमूर्ति (एनआइपीएफपी, नई दिल्ली), प्रो. सुब्रत सरकार, (आइजीआइडीआर, मुंबई), प्रो. सुरेन्द्र कुमार (सीआरआरआइडी, चण्डीगढ़), प्रो. महाजन (पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़), प्रो. चेतन घाटे (आइएसआइ, दिल्ली), प्रो. शलभ (आइआइटी कानपुर)। आप सब ने, आर्थिक नीति निर्माण के लिए सांख्यिकीय अनुसंधान की थ्योरी तथा प्रेक्टिस के क्षेत्र में जो इतनी विशेषज्ञता और अनुभव पाया है, वह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है।

2. सांख्यिकी, देखने और अनुभव करने से, प्रणाली बद्ध रूप से सीखने की एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग सदियों से किया जा रहा है। विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए आर्थिक सांख्यिकी के कंपाइलेशन का कार्य, भारत में बहुत पहले से किया जा रहा है। तथापि पिछले कुछ समय से, आर्थिक सांख्यिकी की गुणवत्ता के बारे में कुछ चिंताएं प्रकट की जाने लगी हैं। इससे आधिकारिक (ऑफिशियल) सांख्यिकी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और अधिक ध्यान देने तथा और संगठनात्मक प्रयास किये जाने की ज़रूरत रेखांकित होती है।

3. सांख्यिकी एक सार्वजनिक हित के लिए है क्यों कि यह नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है। आज अधिकांश आर्थिक विश्लेषण का आधार सांख्यिकी ही है। अंतः एक मजबूत सांख्यिकी आधार और हाथ में व्यापक आंकड़े, एक अच्छे अनुभवजन्य अर्थशास्त्री की मूलभूत पूर्वापेक्षाएं हैं। आज इस सम्मेलन में उपस्थित कई प्रख्यात अर्थशास्त्रियों की उपस्थिति से यह सिद्ध भी हो जाता है। असल में कई प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने तो अपना कैरियर सांख्यिकीशास्त्रियों के रूप में ही शुरू किया था।

4. उदाहरण के तौर पर नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मिल्टन फाइडमैन, जो कि गत सदी के संभवतः सबसे जाने-माने मॉनेटरिस्ट अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी अपना कैरियर वाशिंगटन डी.सी. में एक सांख्यिकीविद के रूप में ही शुरू किया। एक अन्य नोबल पुरस्कार विजेता सीमॉन कुज़नेत्स ने 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी'' की आधारशिला रखकर ''वृहदार्थिक विश्लेषण'' के प्रति एक अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव रखी।

5. केन्द्रीय बैंक आज पहले से कहीं अधिक चुनौती भरे हो गए हैं और विश्वसनीय तथा समयपरक सूचनाएं प्रभावी नीतिनिर्माण की कुंजी बन गई हैं। एक केन्द्रीय बैंक के रूप में, विभिन्न वृहदार्थिक सांख्यिकी निर्मित करने के लिए हम उत्तरदायी हैं। यह सांख्यिकी हमारी नीतियों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में प्राथमिक तथा द्वितीयक, दोनों प्रकार के स्रोतों से एकत्र की जाती है। चूंकि रिज़र्व बैंक के पास देश के सर्वाधिक संख्या में सांख्यिकीविद हैं अतःमैं हमारी संस्था में सांख्यिकीविदों की भूमिका से अपनी बात शुरू करूंगा और डीएसआइएम की उपलब्धियों और चुनौतियों का उल्लेख करूंगा।

6. रिज़र्व बैंक का सांख्यिकीविद कई प्रकार की भूमिकाएं निभाता हैं। डीएसआइएम, मौद्रिक, बैंकिंग, कॉरपोरेट तथा बाह्य क्षेत्रों से संबंधित जानकारियों के एकत्रण, संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार द्वारा सांख्यिकीय सेवाएं प्रदान करता है। इसकेअन्य प्रमुख ध्यानाकर्षण केन्द्र हैं - नीति निर्माण के लिए इनपुट्स प्रदान करना, सर्वेक्षण आयोजित

* 17 मार्च 2012 को चंडीगढ़ में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहंती द्वारा दिया गया अभिभाषण।

करना, तथा बैंक की ज़रूरतों के अनुरूप शोधकार्य करना। इन वर्षों में इसने डाटा एकत्रण तथा प्रसार के अपने स्कोप तथा स्पेक्ट्रम को काफी बढ़ाया है। इस संबंध में एक प्रमुख उपलब्धि है-वेब समर्थित डाटा वेयर हाउस में सुधार, जो शोधकर्ताओं में ''डाटाबेस ऑन इंडियन इकोनोमी'' (डीबीआइई)के नाम से प्रसिद्ध है। आज बैंक के कई अग्रणी डाटा प्रकाशन जैसे ''हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनोमी'' डीबीआइई से ही निकलते हैं। रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर काफी संख्या में डाउनलोडेबल डाटा सार्वजनिक हित के लिए उपलब्ध है और लगभग रिलीज़ के समय ही डाल दिया जाता है। मुझे ख़ुशी है कि डीबीआइई का एक अधिक ''प्रयोगकर्ता मित्रवत रूप'' आज ही रिलीज़ किया जा रहा है।

7. सूचना प्रबंधन और प्रसार हेतु ''ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली'' (ओआरएफएस) के अंतर्गत, डाटा प्रेषण की प्रणाली को और आगे मजबूत किया जा रहा है। इस समय डीबीओडी, डीबीएस,एफईडी, एफएमडी, डीपीएसएस तथा एमपीडी जैसे विभिन्न विभागों की 40 रिटर्न्ज़ इस प्लैटफॉर्म के जरिए ही प्रेषित की जा रही हैं। इसी तरह, वित्तीय डाटा की रिपोर्टिंग में मानकीकरण की 'एक्सटेन्सिबल बिजिनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) परियोजना' ने वर्ष के दौरान काफी प्रगति की है और 42 रिटर्न्ज, कार्यान्वयन हेतु लिए गए हैं।

8. गत एक वर्ष में, विभाग ने, डाटा गैप्स की पहचान करने और उसे भरने के काम में काफी प्रगति की है। इनमें, ''समन्वित प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण (सीडीआइएस) का कार्यान्वयन, जनसंख्या जनगणना तथा आर्थिक जनगणना के साथ मास्टर ऑफिस फाइल (एमओएफ) का विस्तार, बैंकिंग सेवा के लिए सेवामूल्य और उत्पादन सूचकांक का विकास, गृहमूल्यसूचकांक का निर्माण, ग्रामीण मज़दूरी[1] से संबंधित टाइम सीरीज़ डाटा का कोलेशन, तथा आटोमेटिक रूट के अंतर्गत ईसीबी हेतु ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन) की प्रणाली शामिल है।

9. विभाग की अनुसंधान गतिविधियों में मुख्यतः ये शामिल हैं - आर्थिक मापन, विश्लेषण, आर्थिक विकास की मॉडेलिंग, तथा भविष्यकथन, (पूर्वानुमान); स्फीति, कार्पोरेट, परफॉर्मेन्स तथा अन्य वृहदार्थिक संकेतक तथा अग्र-दृष्टि-मौद्रिक-नीति-निर्माण हेतु, प्रत्याशित वृहत डेवलेपमेन्ट्स के प्रति आर्थिक एजेन्टों की प्रतिक्रियाएं जुटाना, विभिन्न एकचर (यूनीवेरिएट) तथा बहुचर मॉडलों के आधार पर ''विकास और स्फीति प्रोजेक्टेड पथ'' फैन चार्ट्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि गत दो वर्षों से स्फीति, रिज़र्व बैंक के 'सहजता-स्तर' से अधिक बढ़ गई है अतः विभाग द्वारा किया गया ''विकास-स्फीति-समझैताकारी-तालमेल'', ''अंशांकित मौद्रिक नीति कार्रवाइयों'' के लिए विशेषकर लाभकारी रहा।

10. विभाग द्वारा आयोजित सर्वेक्षण, खासकर वृहदार्थिक बदलावों पर किए गए सर्वेक्षण, अग्र-दृष्टि मौद्रिक नीति निर्माण के लिए, लगातार मूल्यवान इनपुट्स प्रदान कर रहे हैं। इनमें जो सर्वेक्षण शामिल हैं, वे हैं, - औद्योगिक आउटलुक सर्वे (आइओएस), आदेश पुस्तिकाएं, इन्वेंट्रीज़ तथा क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीकस), क्रेडिट कंडीशन्ज़ सर्वे (सीआरसीएस), परिवारोंका स्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईएसएच) उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) तथा सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्ज़ (एसपीएफ)। इन सर्वेक्षणों में से अधिकांश के मुख्य निष्कर्ष, अब रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जा रहे हैं जिनके साथ-साथ प्रत्येक तिमाही की वृहदार्थिक तथा मौद्रिक गतिविधियाँ भी प्रकाशित की जाती हैं। इससे सर्वे-आउटपुट की दृश्यता बढ़ी है और सर्वेक्षण परिणामों के प्रसार में समयपरकता की दृष्टि से भी काफी सुधार आया है। मुझे यकीन है कि ये सर्वेक्षण लोगों के लिए जाहिर करने से अब इन क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य और भी बढ़ेगा।

11. परिसंपत्ति मूल्य के घटनाक्रम की समझ ने और भी महत्ता हासिल कर ली है, खासकर वैश्विक वित्तीय संकट के बाद। इस संदर्भ में विभाग ने पंजीकरण मूल्याधारित ''हाउस प्राइस सूचकांक'' (एचपीआइ) के संकलन में काफी प्रगति की है। अब इसका फैलाव 9 शहरों तक हो गया है। डीएसआइएम के क्षेत्रीय कार्यालय इस दिशा में काफी योगदान कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त, इसके पूरक के रूप में, विभाग ने, बैंकों के पास उपलब्ध 'आवास-ऋण-खाता-जानकारी' के आधार पर एक परिसंपत्तिमूल्य निगरानी प्रणाली (एपीएमएस) शुरू की है। वित्तीय स्थिरता विश्लेषण, रिज़र्व बैंक का अन्य महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण केंद्र है। मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि विभाग इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और वित्तीय दबाव संकेतकों तथा परिसंपत्ति मूल्यों जैसे इनपुट्स प्रदान कर रहा है।

12. इन उपलब्धियों के होते हुए भी अब मैं विभाग की आगे की राह में आनेवाली चुनौतियों के बारे में चर्चा करूंगा।

पहली चुनौती तो यह है कि वित्तीय संकट के दृष्टिगत, समय पर तथा गुणयुक्त सांख्यिकी की उपलब्धता बहुत आवश्यक हो गई है, सूचना और विश्लेषण संबंधी अपेक्षाएं और विविध हो गई हैं जिसमें

[1] श्रम ब्यूरों के आंकड़ों पर आधारित

वित्तीय स्थिरता पर भी और अधिक बल आ गया है। संरचनात्मक मौद्रिक नीति की सभीक्षाएं जल्दी होने के कारण, उच्चगुणवत्ता वाली और ''शीघ्र-अग्र-दृष्टि-सूचना'' की ज़रूरत और अधिक बढ़ गई है। इसी के साथ-साथ, परिचालनात्मक मुद्दों को सुलझाने में सांख्यिकी के प्रयोग ने भी और अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है। इस घटनाक्रम ने, बैंक के सभी विभागों में, प्रशिक्षित सांख्यिकीविदों की मांग को और अधिक बढ़ा दिया है। यह विभाग, सांख्यिकीविदों की संख्या की दृष्टि से, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आइएसआइ) के बाद, देश का दूसरा सबसे बड़ा हैं और इसे संस्था की, और बेहतर सेवा हेतु, खुद को तैयार करना चाहिए।

दूसरे, देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते, अधिकाधिक संस्था में वृहदार्थिक सांख्यिकी प्रदान करने की हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे प्रकाशनों का एक स्तर है, जिससे हमारे डाटा प्रयोगकर्ताओं में एक विश्वास जगता है। यहां तक कि मूल्य सांख्यिकी जैसे सैकेन्डरी डाटा के लिए भी लोग रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों का इस्तेमाल करना ही बेहतर समझते हैं। अतः आंकड़ों की गुणवत्ता बनाए रखने, उनकी समयपरकता और उनकी सार्थकता की जिम्मेदारी अनिवार्यतः डीएसआइएम की ही बनती है। आंकड़ों की गुणवत्ता के वैधीकरण और उसमें सुधार लाने के लिए विभाग को, प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए।

तीसरे, वृहदार्थिक बदलावों से संबंधित कुछ ऐसे सर्वेक्षण हुए हैं, जो हमारी संतुष्टि के अनुरूप नहीं हुए, हमने व्यापारिक क्षेत्र और नए स्नातकों के लिए रोज़गार अवसरों के संबंध में, आंकड़े एकत्र करने की एक शुरूआत की है। परंतु हमें इसमें और तेज़ी लाने तथा इन सर्वेक्षणों के परिणाम शीघ्र निकालने की कोशिश करनी चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण संकेतक जो, समग्र आर्थिक गतिविधि के लिए शुरूआती संकेत भेजता है, वह है - खुदरा बिक्री। शहरों में खुदरा बिक्री के तिमाही सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालयों की मदद से शुरू किये जाने चाहिएँ।

चौथे, विभाग, रिज़र्व बैंक के बाहर और भीतर, विभिन्न समितियों में अपनी भागीदारी के ज़रिए विभिन्न आंकड़ा अंतरालों ''(डाटा गैप्स) तथा सांख्यिकी मापन के मुद्दों को सुलझाने में भी लगा है। स्फीति गतिशीलता की जटिलता के दृष्टिगत विश्वभर में जिस खास मुद्दे ने फिर से ध्यान आकर्षित किया है, वह है - कीमतों का मापन - जिंसों की क़ीमतें, उपभोक्ता कीमतें तथा परिसंपत्तियों की क़ीमतें। हाल के वर्षों में, भारत में, कीमतों के मापन में सुधार लाने के लिए काफी सांस्थानिक प्रयास हो रहे हैं। अब हमारे पास एक नई सीपीआइ (ग्रामीण, शहरी और मिश्रित) है। डब्ल्यूपीआइ (थोकमूल्य सूचकांक) में भी संशोधन किया गया है। जिन्सों / परिसंपत्ति श्रेणियों, उत्पादन चरणों तथा साथ ही विभिन्न सेक्टरों और क्षेत्रों में मूल्यों और स्फीति के मापन के संबंध में शोध के अतिरिक्त, मूल्यों के आंकड़ों की कवरेज और रिपोर्टिंग में सुधार की भी व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। चूंकि अब हमारे पास अधिक प्रतिनिधिक सीपीआइ श्रृंखलाएँ हैं अतः सांस्थानिक प्रयासों को, एक उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआइ)तथा साथ ही सेवामूल्य सूचकांक कंपाइल करने की ओर दिशा देने की ज़रूरत है।

पाँचवें, क्षेत्रीय बाज़ार समझ और सांख्यिक़ीय समझ, मौद्रिक नीति निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट्स प्रदान करने में, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उदाहरण के लिए बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने एक ''क्षेत्रीय- सांख्यिकीय आंकड़ा एकत्रण प्रणाली'' स्थापित की है, जो 25 संकेतकों को कवर करती है जिसमें कारोबारी स्थितियाँ मूल्य बदलाव, श्रम तथा रोज़गारे भी शामिल है। ये गुणात्मक सर्वेक्षणों से भिन्न है। इस प्रकार एकत्रित की गई सूचनाओं का विश्लेषण कर, इन्हें अंकों (स्कोर्ज़) में रूपान्तरित किया जाता है जो कि बीओई की मुद्रा नीति समिति (एमपीसी) की चर्चाओं में काफी महत्वपूर्ण इनपुट होते है। भारत ऐसा देश है जहाँ काफी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। अतः क्षेत्रीय इनपुट्स, नीतिनिर्माण में काफी मूल्यवान होते हैं। अब इसकी पुनर्गठित संरचना तथा प्रमुख केन्द्रों में, क्षेत्रीय कार्यालयों में, इसकी व्यापक उपस्थिति से, यह विभाग, राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में मदद देने के लिए इसी प्रकार की संबंधित सांख्यिकी तथा बाज़ार समझ जुटाने की एक प्रणाली शुरू कर सकता है जिसमें खासकर मूल्यों तथा कृषिस्थितियों पर अधिक बल दिया जाए ।

छठे, मुद्रा और सिक्कों की मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए डीसीएम के साथ इस समय चल रहे कार्य के एक भाग के रूप में निम्नलिखित से संबंधित क्षेत्रीय सर्वेक्षणों पर भी ध्यान केंद्रित कर उन्हें आयोजित करने की आवश्यकता है (i) सिक्कों / नोटों की उपलब्धता / कमी (ii) क्षेत्रीय प्रथा तथा करेन्सी नोटों का प्रयोग, तथा (iii) प्रणाली में जाली नोटों का अनुमान। इसके अतिरिक्त विभाग को वित्तीय समावेशन संबंधी सर्वेक्षण आयोजित करने में भी सीधा शामिल किया जाना चाहिए खासकर बैंकों के ''आउटरीच कार्यक्रम'' के परिणामस्वरूप गांवों में वित्तीय समावेशन के परिणामों का आकलन करने के संबंध में।

सातवें, केन्द्रीय कार्यालय के कई विभागों विभाग में विभाग की काफी अच्छी उपस्थिति है जैसे बाह्य निवेश और परिचालन विभाग

(डीईआइओ), मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी), आंतरिक कर्ज प्रबंधन विभाग (आइडीएमडी), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआइटी), भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीपीएस) तथा वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू)। यह वांछनीय होगा कि इन विभागों के हमारे अधिकारीगण, नीतिगत और परिचालनात्मक मुद्दों के लिए विश्लेषणात्मक इनपुट्स प्रदान करें और तत्संबंधी शोधपत्र तैयार करें। ये पेपर्ज सम्मलनों में भी पढ़े जा सकते हैं और अंततः रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर्ज सीरीज में भी प्रकाशित किये जा सकते हैं। इससे हमारे संगठनात्मक उद्देश्यों को और आगे ले जाने में यह अनुसंधान और अधिक मूल्यवान सिद्ध होगा।

आठवां: क्षेत्रीय कार्यालयों और इकाइयों में शोध के प्रति इस केन्द्रित और कटिबद्ध दृष्टिकोण को बनाए रखना होगा ताकि विभाग द्वारा हाथ में लिए गए शोधकार्य समय पर पूरे किए जा सकें। आंकड़ों के प्रबंधन और प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी का संपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। एक ''पूर्ण पूर्वानुमान सूट'' विकसित करने के लिए जिसमें डायनेमिक स्टोकैस्टिक जनरल इक्वीलिब्रियम (डीएसडीई) मॉडल भी शामिल हैं। मॉडलिंग तथा पूर्वानुमान क्षमताओं को भी मजबूत बनाने की जरुरत है।

13. अंत में मैं विभाग को इसकी कई उपलब्धियों के लिए बधाई देना चाहता हूँ। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं जिनकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया भी, जैसे कि प्रख्यात सांख्यिकी शास्त्री ने एक बार कहा भी था ''एक अनुमानित समस्या के सही जवाब की बजाय एक सही समस्या का अनुमानित जवाब एक ज्यादा अच्छा सौदा है। ज्यूं ज्यूं हम बहुत से प्रश्नों से जूझते जा रहे हैं त्यूंत्यूं मुझे बैंक में सांख्यिकीय कौशल और सांख्यिकी की मांग बढ़ती नजर आ रही है । मुझे यकीन है कि इस सम्मेलन में होने वाली चर्चाएं, शिक्षा विदों और नीति निर्माताओं को और करीब लाएंगी तथा हमारी सांख्यिकीय विश्लेषण और प्रणाली को अधिक मजबूत बनाएंगी। मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ।